बहला फुसला कर धर्मान्तरण कराने वालों पर कठोर कार्यवाही होगी - भजनलाल

बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित सभास्थल के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा की

बांसवाड़ा, (निसं), 20 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहर के कुशलबाग मैदान में शहरी सेवा शिविर के अवलोकन के दौरान आमजन को संबोधित किया। भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने धर्मान्तरण विधेयक पारित कर दिया है, जिससे बहला फुसलाकर धर्मान्तरण कराने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके। इससे पूर्व शर्मा ने शिविर में

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टीबी मरीजों को किट बांटे, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधी योजना व मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों को चैक सौंपे तथा मंगला पशु बीमा योजना के लाभार्थियों को बीमा पॉलिसी दी।**

लगी स्टालों का अवलोकन किया।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान को विकास की महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं, जिनसे बांसवाड़ा-डूंगरपुर सहित संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में गरीब कल्याण एवं विकास की योजनाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनका जीवन स्तर भी बेहतर बन रहा है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत, शिविरों में माताओं-बहनों की ब्लडप्रेशर, डायबिटीज और कैंसर सहित एनीमिया, टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की जांच भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शहरी सेवा शिविर के लाभार्थियों से संवाद कर विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर योजनाओं की जानकारी भी ली।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत, टीबी मरीजों के परिजनों को निक्षय पोषण किट वितरित की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों को चैक भी सौंपे। साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लाभार्थियों को बीमा पॉलिसी तथा खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे।

मुख्यमंत्री, स्टॉलों के अवलोकन के दौरान, जब अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे तो हाथों-हाथ लोगों ने फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हुए मुख्यमंत्री से वार्ता के लिये बधाईयां दी। पूर्व राज्यमंत्री धनसिंह रावत ने अपने उद्बोधन की शुरूआत में धर्मान्तरण विधेयक के लिये मुख्यमंत्री का आभार जताया वहीं उन्होंने नीमच-प्रतापगढ़ हाईवे को बांसवाड़ा होते हुए दाहोद से जोड़ने, शहीदी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलवाने, दानपुर क्षेत्र को सिंचित करने के लिये लिफ्ट योजनाएं बनवाने एवं स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में अवसर दिलवाने के लिये कोटे में कोटा को लागू करवाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में "शहरी सेवा" शिविर को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया और विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर योजनाओं की जानकारी भी ली।

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने के लिए कदम उठाए। वहीं, मुख्य सचिव भी एक्ट के प्रावधानुसार हर जिला स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करें। यह अधिकारी कलेक्टर या अपर कलेक्टर स्तर के हो सकते हैं। यह अफसर एक्ट की धारा 6 के प्रावधानों को लागू कराएंगे। खंडपीठ ने कहा कि हर जिले में उठाए गए कदमों की पालना रिपोर्ट आगामी सुनवाई 12 नवंबर से पहले अदालत में पेश की जाए। इसके अलावा, केन्द्र सरकार के अधिवक्ता भी एक रिपोर्ट पेश कर बताएंगे कि उन्होंने क्या कदम उठाए और कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक किया है। सुनवाई के दौरान एडि. एसपी सीमा भारती ने कहा कि ई-सिगरेट को जब्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गये हैं और केन्द्र सरकार की ओर से भी वेबसाइटों को ब्लॉक किया जा रहा है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि ई-सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। पीआईएल में ई-सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाए जाने और एक्ट 2019 के प्रावधानों को लागू करने की गुहार की गई है।

समुद्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इंजीनियरिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि 4.8 किलोमीटर लंबे सुरंग खंड पर हासिल की गई है। इससे जुड़े इंजीनियरों के अनुसार घनसोली और शिलफाटा की ओर से एक साथ खुदाई का काम शुरु किया गया और दोनों तरफ से पानी के नीचे के हिस्से के भू भाग पर सुरंग का चुनौतीपूर्ण निर्माण किया जिसमें भारतीय इंजीनियरिंग को आज सफलता मिली है। रेलवे ने इस सफलता को ऐतिहासिक बताया और कहा कि भारत में समुद्र के नीचे सुरंग का यह पहला निर्माण है जो खाड़ी के अवरोध को तोड़कर मुंबई और ठाणे को जोड़ेगी।

'मुस्लिम अगर खर्च नहीं उठा सकते तो ज्यादा शादियां भी नहीं कर सकते'

केरल हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला की भरण पोषण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की

तिरुअनंतपुरम, 20 सितंबर। केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है तो उसे दूसरी या तीसरी शादी करने का कोई हक नहीं है, यहां तक कि, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत भी।

कोर्ट ने ये टिप्पणी 39 साल की महिला की याचिका पर सुनवाई को दौरान की, जब उसने कोर्ट में अपने पति से 10 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता मांगने के लिए याचिका दायर की, जो कि भीख मांगकर गुजारा करता है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका 46 वर्षीय नेत्रहीन पति, जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है, उसे छोड़कर पहली पत्नी के साथ रह रहा है और अब तीसरी शादी करने की धमकी दे रहा है।

कोर्ट ने कहा कि यह सच है कि प्रतिवादी मुस्लिम समुदाय से है और वह अपने पारंपरिक कानून का लाभ उठा रहा है, जो, उसके अनुसार, उसे दो या तीन बार शादी करने की अनुमति देता है। जो व्यक्ति दूसरी या तीसरी पत्नी का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, वह मुसलमानों के पारंपरिक कानून के अनुसार भी दोबारा शादी नहीं कर सकता।

- **महिला का पति नेत्रहीन है और भीख मांगता है उसने दो शादियां कर रखी हैं और तीसरी शादी करने की धमकी दे रहा है।**
- **कोर्ट ने कुरान की आयतों का हवाला दिया कि कोई व्यक्ति अगर अपनी एक से ज्यादा पत्नियों के साथ न्याय कर सकता है तभी एक से ज्यादा शादियां कर सकता है।**

अदालत ने आगे कहा कि उस व्यक्ति की लगातार शादियां, जब वह केवल एक भिखारी था, मुस्लिम प्रथागत कानून के तहत भी स्वीकार नहीं की जा सकतीं।

अदालत ने कहा, "मुस्लिम समुदाय में इस तरह की शादियां शिक्षा की कमी और मुसलमानों के प्रथागत कानून की जानकारी के अभाव के कारण होती हैं। कोई भी अदालत किसी मुस्लिम व्यक्ति की पहली, दूसरी या तीसरी शादी को तब मान्यता नहीं दे सकती, जब वह अपनी पत्नियों का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो और उसकी पत्नियों में से एक ने भरण-पोषण की मांग वाली याचिका दायर की हो।" कुरान की आयतों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि यह पवित्र ग्रंथ एक विवाह प्रथा का प्रचार करता है और बहुविवाह को केवल एक अपवाद मानता है। अदालत ने कहा, "अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी और चौथी पत्नी को न्याय दे सकता है, तो एक से ज्यादा बार शादी करना जायज़ है।"

सुनवाई के दौरान, कोर्ट की अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, अधिकांश मुसलमान एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, जो कुरान की सच्ची भावना को दर्शाता है, जबकि केवल एक छोटा तबका ही बहुविवाह करता है, और कुरान की आयतों को भूल जाता है। अदालत ने कहा कि उन्हें धार्मिक नेताओं और समाज द्वारा शिक्षित किया जाना चाहिए।

अदालत ने निर्देश दिया कि उचित कार्रवाई के लिए उसके आदेश की एक प्रति समाज कल्याण विभाग के सचिव को दी जाए। "विभाग को प्रतिवादी को परामर्श प्रदान करना चाहिए, जिसमें धार्मिक नेताओं सहित, सक्षम परामर्शदाताओं की सहायता ली जाए।"

ट्रंप का एच-1बी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अध्ययनों द्वारा असमर्थित लगेगा, तो इसे रद्द किया जा सकता है। साथ ही, कांग्रेस भी यह दावा कर सकती है कि इतनी व्यापक नीति में बदलाव कार्यपालिका की शक्तियों के दायरे से बाहर है। व्यवसाय जगत ने इस निर्णय को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। तकनीकी दिग्गज और विदेशी इंजीनियरों पर निर्भर अमेरिकी कंपनियाँ चेतावनी दे रही हैं कि यह कदम नवाचार को बाधित करेगा, संचालन को विदेशों में ले जाएगा और अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त को कमज़ोर करेगा।

भारत, जो एच-1बी वीज़ा धारकों का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखता है, इस निर्णय से सबसे अधिक प्रभावित होगा। भारत के आईटी सेवा और आउटसोर्सिंग क्षेत्र को अब भारी लागत का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। अतीत में, वीज़ा शुल्क में कोई भी बदलाव हमेशा दस्तावेज़ी प्रशासनिक खर्चों से जुड़ा रहा है, न कि किसी दंडात्मक मूल्य निर्धारण से। जब तक ट्रंप प्रशासन विश्वसनीय तरीके से यह साबित नहीं करता कि यह 100,000 डॉलर शुल्क वास्तव में वीज़ा आवेदन की जाँच की लागत को दर्शाता है, तब तक अदालतों द्वारा इसे अधिकारों का दुरुपयोग माने जाने की संभावना है।

फिलहाल, इस घोषणा से अमेरिकी आव्रजन नीति (इमिग्रेशन पॉलिसी) में भारी अनिश्चितता पैदा हो गई है। अमेरिकी कंपनियों और हजारों उन विदेशी पेशेवरों के लिए, जो एच-1बी कार्यक्रम को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में प्रवेश का मार्ग मानते हैं, यह एक बड़ा झटका है।

चपरासी भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

झाझरिया (25) निवासी खंडेला जिला सीकर है और जो मुरलीपुरा जयपुर इलाके की आईएएस कॉलोनी में परिवार के साथ रहता है। उसने बीटेक (इंजीनियरिंग) कर रखी है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में उसका अशोक नगर स्थित महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में परीक्षा सेंटर आया था। वह तमाम सुरक्षा इंतजाम को चकमा देकर सेंटर के भीतर डिवाइस ले जाने में कामयाब रहा।

थानाधिकारी ने बताया कि पहली पारी में परीक्षा देने पहुंचा आरोपी रवि अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर ले गया। परीक्षा के दौरान सुबह करीब 10:30 बजे उसने स्मार्ट वॉच के कैमरे से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर वॉट्सऐप के जरिए सेंटर से बाहर भेजी। उसकी संदिग्ध हरकतों को देखकर परीक्षा हॉल में मौजूद केन्द्र अधीक्षक को शक हुआ। बार-बार पूछने के बावजूद, अभ्यर्थी किसी भी डिवाइस के होने से इनकार करता रहा। लेकिन जब केन्द्र पर मौजूद पुलिस और केन्द्र अधीक्षक ने पूछताछ की तो आरोपी घबरा गया। इसके बाद जब अभ्यर्थी रवि कुमार झाझड़िया की तलाशी ली गई तो अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच मिली। शुरुआती पूछताछ में अभ्यर्थी का कहना है कि उसने सोचा कि गूगल पर कठिन सवाल डालकर, उसके उत्तर हासिल कर लेगा। लेकिन उसे इसका मौका नहीं मिला। जांच में साफ हो गया कि उसने प्रश्नपत्र बाहर भेजा है। पुलिस ने आरोपी रवि को तुरंत राउंड-अप कर स्मार्टवॉच और वाट्सएप पर भेजे पेपर के बारे में पता कर उसके घर पर मिले मोबाइल को भी जब्त कर किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई और साथ ही उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा।

'विश्व में हमारा एक ही शत्रु है, वह है दूसरे देशों पर निर्भरता'

प्रधानमंत्री मोदी ने भावनगर में एक सभा में कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाया कि वो आज़ादी के बाद देश की औद्योगिक व व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ा नहीं पाईं

नई दिल्ली, 20 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को गुजरात के भावनगर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित किया और कहा, भारत आज विश्वबंधुत्व की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता...। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना ही होगा।

जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता... उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए... दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर या उनकी निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते। भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। सौ दुखों की एक ही दवा है और वह है आत्मनिर्भर भारत, इसलिए हमें चुनौतियों से टकराना होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने खड़ा होना होगा।

- **प्र.मंत्री ने कहा, पहले तो कांग्रेस सरकारों ने लाइसैंस राज में उलझाया, जिसने देश को दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दूर कर दिया और फिर उदारीकरण के दौर में आयात पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता रखी गई।**
- **प्रधानमंत्री ने कहा, दूसरों पर निर्भर रहने से आत्म सम्मान आहत होता है। सौ दुःखों की एक दवा है, आत्म निर्भरता।**

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया, इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया, जिसके हम हकदार थे। इसके दो बड़े कारण रहे- लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग-थलग रखा। कांग्रेस सरकार की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 2047 तक हमें विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा... इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए- चिप हो या शिप..., हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत समुद्री क्षेत्र में भी नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म करने जा रहा है। इसी सोच के साथ वन नेशन, वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस लागू किया जाना है। भारत को सबसे बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए तीन बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है और आने वाले वर्षों में इस पर 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। देश के समुद्री क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ है... अब सरकार ने बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दे दी है।

अलविदा मिग-21, 26 सितम्बर को होगी विदाई

नयी दिल्ली, 20 सितम्बर। छह दशक से भी लंबे समय तक भारत की हवाई सीमाओं के प्रहरी रहे और 1965 की लड़ाई से लेकर अभी तक के सभी छोटे-बड़े सैन्य अभियानों में शौर्य और पराक्रम की गाथा लिखने वाले मिग-21 यानी मिकोयान-गुरेविच-21 लड़ाकू विमान को आगामी 26 सितम्बर को वायु सेना अलविदा कहने जा रही है। पिछले दशक तक भारतीय वायु सेना की रीढ और उसके लड़ाकू विमान के बेड़े की

- **भारतीय वायुसेना ने एक्स पर जानकारी दी कि चंडीगढ़ एयरबेस से मिग-21 की विदाई होगी**

शान रहा यह विमान सैन्य विमानन के क्षेत्र में शौर्य और पराक्रम की छह दशक से भी लंबी ऐसी विरासत छोड़ जायेगा जिसे भूला पाना नामुमकिन होगा। मिग-21 ने अपनी ताकत, फुर्ती और सटीक हमलों से भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता और उसकी शक्ति को नया आयाम दिया।

वायु सेना ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में मिग-21 विमान लड़ाकू विमान को आगामी 26 सितम्बर को अपने बेड़े से विदा करने का ऐलान किया। वायु सेना ने कहा है कि इस लड़ाकू विमान ने अपनी ताकत और पराक्रम से राष्ट्र के गौरव को आसमान तक पहुंचाया।

अभिनेता मोहनलाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शनिवार को बताया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर मोहनलाल को यह पुरस्कार दिया जायेगा। उन्हें यह सम्मान मंगलवार को 71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जायेगा। मोहनलाल ने अपने साढ़े चार दशक के सिने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। वह सिर्फ मलयालम ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगू और हिंदी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जादू बिखेर चुके हैं। उन्हें पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से भी नवाजा गया है। भारतीय सेना भी उन्हें ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद देकर सम्मानित कर चुकी है, जो किसी भी अभिनेता के लिए गौरव की बात है।

मोहनलाल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1980 में फिल्म मंजिल विरिंजा पूक्कल से की थी। यह फिल्म भले ही एक रोमांटिक ड्रामा थी, लेकिन मोहनलाल ने इसमें विलेन की भूमिका निभायी थी। उनके अभिनय को इस कदर सराहा गया कि उन्हें लगातार निगेटिव रोल मिलने लगे, लेकिन एक सच्चा कलाकार कभी एक ही फ्रेम में नहीं बंधता।कुछ सालों के भीतर उन्होंने अपने किरदारों की विविधता दिखाते हुए कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन जैसी शैलियों में खुद को साबित किया।

ईडी को मो. सादिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संदिग्ध है। हालांकि, उसके पास कोई वैध और पर्याप्त व्यक्तिगत आय नहीं पाई गई, फिर भी उसने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश, ईरान, ओमान, नेपाल, कतर आदि कई देशों की कई बार यात्राएं कीं और इन देशों में लंबे समय तक रहा। तलाशी के दौरान बांग्लादेश में एक एनजीओ को वित्तीय सहायता देने के साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि 3 जनवरी 2022 को कोटगेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। ईडी को सादिक के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने में सादिक की संलिप्तता पाई गई है। इसमें इज़रायली झंडे को जलाने के वीडियो भी शामिल हैं। इसके पीछे उसका उद्देश्य सहानुभूति प्राप्त कर अवैध गतिविधियों के लिए धन जुटाना था।

जयपुर सेंट्रल जेल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शिफ्ट में इन प्रहरियों की अलग-अलग प्वॉइंट्स पर ड्यूटी थी। परंतु गश्त के दौरान हुई लापरवाही का फायदा उठाकर दोनों कैदी जेल से भाग निकले थे। पुलिस महानिदेशक जेल (डीजी) गोविंद गुप्ता ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जेल विक्रम सिंह को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जेल विभाग के आला अधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस जानकारी में सामने आया कि बंदी अनस चोरी के अलावा घर में घुसपैठ के तीन मामलों में सजा काट रहा था और वहीं नवल किशोर चोरी के 7 मामलों में आरोपी है। उस पर अन्य कैदियों के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप भी है। यह घटना दिखाती है कि दोनों बदमाशों ने सेंट्रल जेल से भागने की पूरी साजिश पहले से ही रच रखी थी। जेल के अंदर सुरक्षा-बैरिकेड्स और उन पर तैनात जेल प्रहरियों को चकमा देते हुए पानी का पाइप चुराया। इसके बाद इस पाइप की मदद से 27 फीट ऊंची दीवार फांदकर और हाईटेंशन बिजली के तारों से बच कर निकल भागे।

दिल्ली के कई स्कूलों को फिर बम की धमकी

नयी दिल्ली, 20 सितंबर। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह फिर एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी सुबह करीब साढ़े नौ बजे फोन कॉल्स और संदेशों के माध्यम से मिली, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमकी पाने वाले स्कूलों में डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, सर्वोदय विद्यालय और सर्वोदय को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब मीनार (महरौली) शामिल हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि नजफगढ़ इलाके के स्कूलों को भी धमकी की कॉल प्राप्त हुईं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड और स्वान दस्ता मौके पर पहुंच गई।

ट्रंप ने भारतीय प्रोफैशनल्स पर सर्विस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर प्रभावित हो सकते हैं।

यह ताज़ा झटका ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए कुल 50 प्रतिशत भेदभावपूर्ण टैरिफ के बाद आया है। डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत का मनमाना "रैसिप्रोकल टैरिफ" लगाया था और बाद में भारत द्वारा रूसी कच्चा तेल और ऊर्जा उत्पादों का निरंतर आयात करने पर 25 प्रतिशत का एक और टैरिफ लगा दिया है।

हालाँकि, डॉनल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई, रूसी कच्चा तेल आयात करने पर चीन पर ऐसा ही टैरिफ लगाने की। वास्तव में, चीन द्वारा रूसी तेल का आयात, भारतीय आयात से कहीं अधिक है।

भारत के प्रति भेदभाव को और स्पष्ट करने के लिए, ट्रंप ने रूसी कच्चे तेल और ऊर्जा उत्पादों के आयात के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों की आलोचना की है, लेकिन उन पर सैकेण्डरी सैंक्शन लगाने का साहस नहीं दिखाया है। इसके बजाय, उन्होंने यूरोपीय देशों से भारत और चीन पर हायर सैकेण्डरी टैरिफ लगाने के लिए जोर डाला है।

असल में ट्रम्प के ऐसे निरंकुश और मनमाने फैसले यह दर्शाते हैं कि ट्रम्प के शासन में अमेरिका के साथ किसी समझौते की उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण है और बेहतर है कि समय बीतने का इंतज़ार किया जाए।

लेकिन सबसे पहले, इस नए कदम का सीधा असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, जिनके पास बड़ी अमेरिकी कंपनियों के साथ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर ऑपरेशनल सेवाओं के बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। यह सर्वविदित है कि एच-1बी वीज़ा का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारतीय प्रोफेशनल्स को ही मिलता रहा है, जो अमेरिकी कंपनियों और भारतीय सेवा प्रदाताओं, दोनों के लिए काम करते हैं।

इन नई शर्तों के कारण भारतीय सेवा कंपनियों, मुख्यतः टी.सी.एस., विप्रो, टैक महिन्द्रा, इन्फोसिस और कई अन्य कंपनियों को तुरंत अपने कामकाज को भारत में वापस लाने की ज़रुरत पड़ेगी। इसके अलावा, कई अमेरिकी टैक्नॉलजी दिग्गजों को भी भारत में अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाना होगा, जहाँ उनका काम भारत और अन्य देशों के प्रोफैशनल कर रहे हैं।

असल में यह नया नियम अमेरिका को दी जाने वाली भारत की सेवाओं पर सीधा टैक्स है। अब तक इस पर टैक्स लगाने की चर्चा तो होती रही थी, लेकिन सीधे कर नहीं लगाया गया था। अब, जबकि अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर दिया है तो भारत को भी अमेरिकी सेवाओं के भारतीय आयात पर कर लगाना चाहिए।

अब समय आ गया है कि भारत चुप नहीं बैठे, बल्कि अमेरिका से आने वाले महंगे आयात, जैसे विमान, पर शुल्क लगाए और विमान जैसे बेहद महंगे आयातों को प्रतिद्वंद्वी स्रोतों से आयात करने से भी दूर रहे। इस प्रकार, बोइंग विमानों के बजाय, भारतीय एयरलाइन ऑपरेटरों को बोइंग के यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी, यानी एयरबस इंडस्ट्रीज, की ओर रुख करने के लिए कहा जाना चाहिए।

दूसरी ओर, इस कदम को भारत के आईटी क्षेत्र और ज्ञान आधारित गतिविधियों के स्थायी पुनर्गठन के संकेत के रूप में लिया जाना चाहिए। विदेशों में काम करने की कोशिश करने के बजाय, भारतीयों को देश में ही काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

अमेरिका में काम करने वाले प्रौफेशनल्स के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को, देश में इन प्रतिभाओं को आकर्षित करने के एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उच्च तकनीक और ज्ञान आधारित उद्योगों के लिए जरूरी ढांचा और माहौल देश के अंदर जल्द से जल्द तैयार करना होगा, ताकि ये प्रतिभाएं यहीं काम कर सकें। एक तरह से, यह होना ही है, क्योंकि अमेरिका से विस्थापित पेशेवरों को कुछ फलदायी और संतोषजनक नौकरियों और अवसरों की तलाश करनी होगी। ये लोग भारत में इनोवेशन बेस्ड इण्डस्ट्रीज के विकास और वृद्धि के लिए जरूरी, नई ऊर्जा और जोश लेकर आएंगे।

इस देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रतिभाशाली छात्र, जो अब तक अमेरिका जाते रहे हैं, उन्हें अपने जीवन पर पुनर्विचार करना होगा और सोचना होगा कि वे अपनी धरती पर ही अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर, सरकार को इन प्रतिभाशाली युवाओं को अपने देश में ही बेहतर, फलने-फूलने के लिए उपयुक्त वातावरण और सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।

इसका दूसरा असर यह होना चाहिए कि भारत ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में उभरे। वर्ल्ड इन्टलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा तैयार एक सूचकांक के अनुसार, भारत पहले से ही नवाचार के लिए चिह्नित देशों में से एक है। इसे और आगे बढ़ाने और विकसित करने के लिए, आवश्यक सुविधाएँ और वातावरण तैयार करना होगा।

लेकिन इस नए शुल्क का सबसे बड़ा व्यक्तिगत झटका उन भारतीय कामगारों को लगेगा, जो वर्षों से अमेरिका में काम कर रहे हैं और वहीं बस चुके है, भले ही वे अमेरिकी नागरिक न बने हों। उनकी पूरी जिंदगी उखड़ जाएगी और उन्हें दोबारा अन्यत्र बसना पड़ेगा।

बंगाल में उद्योग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राज्य के औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए की थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के शासन में भी स्थिति बदली नहीं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार, 2011 से 2025 के बीच 6600 कंपनियां, जिनमें से 110 सूचीबद्ध कंपनियां थीं, राज्य छोड़ चुकी हैं।

इस स्थिति को और जटिल बना दिया है कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और अवैध घुसपैठ की बढ़ती समस्या ने। हज़ारों मज़दूर, जो अपनी नौकरियाँ खो चुके हैं, आज सरकारी सहायता पर निर्भर हैं।

ऐसे संकट में सरकार से आक्रामक औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की उम्मीद थी, पर उद्योगों को मिला विश्वासघात। आर्थिक सिद्धांत कहता है कि प्रोत्साहन योजनाएं बाजार की विफलताओं के समय आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक होती हैं - विशेष रूप से तब, जब श्रम समस्याएं, सामाजिक अशांति और कानून-व्यवस्था की चुनौतियाँ सामने हों, जैसा कि पश्चिम बंगाल में स्पष्ट रूप से हो रहा है।

केन्स के आर्थिक सिद्धांत के अनुसार, मंदी के समय सरकार को सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। यही विचारधारा ग्रेट डिप्रेशन के समय कारगर साबित हुई थी और 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट में पुनः सुर्खियों में आई। वर्तमान समय में, जब राज्य की अर्थव्यवस्था पर अंधेरे, बादल मंडरा रहे हैं, तब पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रोत्साहन देने की बजाय, प्रोत्साहन हटा दिए, यह न केवल अजीब निर्णय है, बल्कि आत्मघाती भी।

एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन कंपनियों को सब्सिडी मिली थी, वे 61.3 प्रतिशत अधिक प्रोडक्टिव थीं। इससे यह साबित होता है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियाँ वास्तव में दीर्घकालिक लाभ देती हैं। अमेरिका में भी, राज्य और स्थानीय सरकार हर साल 30 बिलियन डॉलर्स व्यवसायिक टैक्स प्रोत्साहनों पर खर्च करती हैं। यह राजकोषीय गुणक की तरह काम करता है, सरकार द्वारा दिए गए एक रुपये से, दो रुपये से अधिक का लाभ होता है।

भारत सरकार भी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना चला रही है, जिसकी कुल लागत 1.97 लाख करोड़ है। इस योजना के तहत अभी तक 1.76 लाख करोड़ का निवेश साकार हुआ है और बड़े पैमाने की इलेक्ट्रॉनिक्स में विदेशी पूँजी निवेश में 254 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जहाँ केन्द्र सरकार विदेशी पूँजी निवेश और औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए आक्रामक प्रयास कर रही है, वहाँ पश्चिम बंगाल सरकार, भारत की विकास यात्रा में बाधाएं खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा।